reimbursement of share capital to the Government of Maharashtra to avoid delays in implementation of sugar factories in the cooperative sector?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR) and (b) Yes, Sir.

(c) During 1990-91 an amount of Rs. 8 crores was provided to NCDC. For . the year 1991-92 a provision of Rs. 30.00 crores, has been made for providing share capital contribution for Sugar Factories in the cooperative sector. Keeping in view the problems relating to viability and availa bility of required finances for Cooperative Sugar Factories, Government of Maharashtra was advised by NCDC on 25-2-91 not to go ahead with placing of orders for plant and machinery for 27 new Coopera tive Sugar Factories to avoid time and cost over-runs. • . •

Setting up of *a.* Steel Plant in Daitari in Orissa

293. SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY:
SHRI SARADA MOHANTY:

Will the Minister of STEEL be pleased to state: :

(a) whether Government have received any proposal from the Government of Orissa for setting up of a steel plant at Daitari in Orissa in the joint sector; and

(b) if so, by when Government propose to issue license and the reasons, if any, for delay in issuing licence.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (INDEPENDENT CHARGE) (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) M/s. Industrial Promotion and Investment Corporation of Orissa Ltd., a State Government Undertaking of the Government of Orissa, has submitted an application for a Letter of Intent for setting up of a 3 million tonne per annum steel plant at Sukinda Tehsil, District Cuttack, Orissa, in the joint sector.

(b) The proposal was under examination. However, in view of the recent amendments in the licensing requirements, issue of L.O.I. for industrial licence would not be necessary.

अम्बेडकर आवास योजना के अधीन फ्लैटों का आवंटन

*294. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम:** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के लिय करीब दो वर्ष पूर्व विशेष रुप से लागू की गई अम्बेडकर आवास योजना के अधीन फ्लैटों के आवंटन हेतु कोई ड्रा निकाला गया है; और यदि हां, तो इस योजना के अधीन कितने लोगों को फ्लैट आवंटित किये गये हैं; और आवंटितियों का वर्गवार विवरण क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) ऐसा ड्रा कब तक निकाले जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या आवेदनकर्ताओं से कोई अतिरिक्त राशि एकत्रित की गई है: यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) अम्बेडकर आवास योजना में दो ड्रा निकालने का विचार है—पहला, सफल पंजीकृत व्यक्तियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए और दूसरा, फ्लैटों के आवंटन के लिए। इनमें से अभी तक कोई भी ड्रा नहीं निकाला गया है और फ्लैटों का आवंटन नहीं किया गया है । यह मुख्यत: उच्च न्यायालय से स्थगनादेश और आवेदनों पर कार्यवाही में लगे समय की वजह से है ।

(ग) सफल पंजीकृत व्यक्तियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए